THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : Assam State Industrial Development Corporation (ASIDC) was granted a letter of Intent dated 25-1-91 for a Gas Cracker Project in Assam. Work on setting up of the project can start after the Corporation has selected its joint collaborator, arranged funds and prepared a detailed feasibility report for the project.

Compensation claims of Bhopal Gas Victims

1188. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of compensation claims of Bhopal Gas Victims settled during the last two months;

(b) the reasons for slow progress ; and

(c) the measures Govenment propose to take to expedite the settlement of claims ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : (a) to (c) No payment against compensation claims has been made during the last two months due to a few Deputy Commissioners joining duty. Work will progress speedily when all the 40 Deputy Commissioners take up position.

भोपाल गैस पीड़ितों को राहत राशि का वितरण करने में विलम्ब

1189. श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री एन० ई० बलराम :
डा० जैड० ए० अहमद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल गैस पीड़ितों में राहत राशि के वितरण के लिए दिशा-निदश निर्धारित करने में सरकार द्वारा किए जा रहे विलम्ब के कारण राहत राशि के वितरण का कार्य रुका हुआ है, यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई समय सीमा निर्धारित की थी, यदि हां, तो इस संबंध में वह समय सीमा क्या थी, वह कब समाप्त हो गई थी तथा उसका पालन न किये जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजे संबंधी दावों का निपटारा करने के लिए 3 फरवरी, 1992 तक कम से कम 40 दावा अधिकरणों द्वारा कार्य करना आरंभ हो जाना चाहिए था ।

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अभी तक बहुत कम दावा अधिकरण ही खोले गए हैं तथा जिन न्यायालयों ने कार्य करना आरम्भ कर भी दिया है उनके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अभाव में वास्तव में कोई काम नहीं हैं; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस राहत राशि का वितरण आगामी मार्च में कर दिया जाये ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) नौ न्यायिक अधिकारियों को कल्याण आयुक्त, अतिरिक्त/उपायुक्तों के रूप में नियुक्ति कर दी गई है । मार्गदर्शी रूपरेखाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार का कल्याण आयुक्त को निर्देशात्मक मार्गदर्शी रूपरेखायें जारी करने का प्रस्ताव है जिन्हें वह विस्तृत आंतरिक मार्गदर्शी रूपरेखायें तैयार करते समय ध्यान में रख सकेंगे । अधिनिर्णय की कार्यवाहियां आरंभ हो गई हैं ।

(ङ) दावों की संख्या 6 लाख से अधिक है । अधिनिर्णय में अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया शामिल होती है, अतः मार्च मास में मुआवजा राशि वितरित करना संभव नहीं होगा । कुछ पीड़ित जिनके मामले में अधिनिर्णय हो जायेगा, को मार्च, 1992 में भुगतान मिल सकता है ।

Wheat supplied to PDS in Delhi

1190. SHRI RAM NARESH YADAV : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) The quantity of wheat released in the recent months of December and January to the public distribution system in Delhi;

(b) whether it is a fact that taking into consideration the paucity of essential commodities, the quantum of wheat has been increased in the month of February, 1992, if so, what is its impact on rising of prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) The allocation of wheat to the Union Territory of Delhi for distribution System, (PDS) was 64,800 tonnes each for the months of December, 91 and January, 92. For the months of February and March, 92, allocation of 72,000 tonnes of wheat per month has been made. Allocation of foodgrains to States/UTs including Delhi is made taking into account the overall stock position in the Central pool, market availability and *inter-se* requirements of various States/UTs. Increased allocation for PDS do have a sobering effect on rising trend of prices of these commodities in the open market.

Raids against hoarders of essential commodities

1191. SHRI SURESH KALMADI :
SHRI BHUBANESWAR KALITA :
DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have directed the States and Union Territories to further intensify the dehoarding operations to bring down the prices of essential commodities;

(b) how many raids have been conducted from 1st January, to 15th February, 1992 for unearthing the hoarding stock of essential commodities; and

(c) the number of arrests made, prosecutions launched and the value of goods recovered as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Reports from the State Governments/UT Administrations, received upto 15-2-1992, indicate that 14,179 raids were conducted, 501 persons arrested, 393 persons prosecuted and goods worths Rs. 6004·14 lakhs seized during the period 1-1-1992 to 15-2-1992.

Adulteration and diversion of edible oil

1192. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the new